* 20th Year
* Issue: 133
* 16.09.2026 (WEDNESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

डीआरडीओ और इंडस्ट्री साझेदारी से भारत बनेगा डिफेंस हब-राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) और इंडस्ट्री के बीच साझेदारी में भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की क्षमता है। नई दिल्ली में DRDO -इंडस्ट्री सिनर्जी मीट, 'विमर्श 2026' में बोलते हुए, सिंह ने ज़ोर दिया कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम सिर्फ़ सरकार या DRDO अकेले नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। राजनाथ ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए DRDO आज सबसे बड़ी संस्था है। लेकिन यह भी सच है कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ़ सरकार या DRDO की कोशिशें काफ़ी नहीं हैं। यह मिलकर की जाने वाली कोशिश है। और यही सहयोग इस 'विमर्श 2026'

का मुख्य संदेश है। DRDO और इंडस्ट्री के बीच साझेदारी ही भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बना सकती है। सिंह ने रक्षा क्षेत्र में हाल ही में हुए सुधारों, जैसे कि पॉज़िटिव इंडिजनाइज़ेशन लिस्ट (स्वदेशीकरण की सूची), %मेक इन इंडिया% पहल, iDEX, ADITI और रक्षा R&D बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र को देने जैसे कदमों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इन कदमों का मकसद रक्षा आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना है।

उन्होंने आत्मनिर्भरता के विचार को विस्तार से समझाते हुए कहा कि जब मैं आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि हम यहाँ कुछ पुर्ज़े, कुछ मिसाइलें, कुछ हथियार और प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं। आत्मनिर्भरता हमारे चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए। यह हमारे नज़रिए का हिस्सा होनी चाहिए।

जिस देश के पास अपनी तकनीक होती है, उसके पास अपना भविष्य तय करने की ताकत भी होती है। इसलिए, हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी चेतना में आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस साझेदारी में शामिल एक-दूसरे की पूरक ताकतों के बारे में बताया-ष्ठक्रष्ठह्र के पास ज्ञान और तकनीक है, इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता देती हैं, स्टार्ट-अप्स इनोवेशन और तेज़ी लाते हैं, और युवाओं के पास नए भारत का विज़न है। उन्होंने भरोसा जताया कि %विमर्श 2026% की चर्चाओं के नतीजे लैबोरेटरी, इंडस्ट्रीज़, स्टार्ट-अप्स और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचेंगे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मज़बूती बढ़ेगी। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि विमर्श 2026 से निकली चर्चाएँ लैबोरेटरी, इंडस्ट्रीज़, स्टार्ट-अप्स और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचेंगी; और आखिर में, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती में साफ़ तौर पर दिखेंगी। हमारी चर्चाएँ सिर्फ़ विकास की बातें न करें; बल्कि विकास का रास्ता भी बनाएँ। और यही विमर्श 2026 की सबसे बड़ी कामयाबी होगी।

बिहार बाढ़ पर बड़ा एक्शन, सम्राट चौधरी ने जारी किए ५७१ करोड़ के राहत कोष

पटना १५/०९ (संवाददाता): बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 सितंबर को पब्लिक सर्वेंट्स रेजिडेंस के 'संकल्प' ऑडिटोरियम में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बांटने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में सीधे ?579.23 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हर परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए 7,000 मिले। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया था, जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्लय ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों, चल रहे राहत और बचाव कार्यों, और प्रभावित लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश की। वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि बाढ़ की गंभीर स्थिति में राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित परिवारों

को तुरंत राहत, मदद और सुरक्षा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से 21 शहरों के 136 वार्ड, 2,642 गाँव, 575 ग्राम पंचायत, 88 ब्लॉक और 15 ज़िलों में लगभग 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी से लगभग 55,000 हेक्टेयर ज़मीन और फ़सलें बर्बाद हो गई हैं। सभी स्तरों पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। नागरिकसेवाएं पाएं

चौधरी ने बताया कि 1,200 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जिनसे प्रभावित लोगों को लगभग 1.28 करोड़ बार खाना खिलाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों में खाना, पीने का पानी, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की लगातार सप्लाई सुनिश्चित की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (हृष्ठक्रस्न) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (स्ष्ठक्रस्न) की 21 टीमें राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। चौधरी ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने तक मदद जारी रहेगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की मां हसीरानी रथ को भाजपा का नंदीग्राम टिकट

कोलकाता १५/०९ (संवाददाता): बीजेपी नंदीग्राम उपचुनाव के लिए हसीरानी रथ को अपना उम्मीदवार घोषित किया। हसीरानी रथ, सुवेंदु अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की माँ हैं, जिनकी मई में हत्या कर दी गई थी। पार्टी ने रेजीनगर विधानसभा सीट के लिए मुर्शिदाबाद ज़िले के अपने पूर्व अध्यक्ष सखाराव सरकार को भी उम्मीदवार बनाया। रथ ने पार्टी का आभार जताया और पत्रकारों से कहा कि उन्हें जीत का भरोसा है। उन्होंने इस सीट को रिकॉर्ड 1.1 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा है। रथ ने कहा कि नंदीग्राम संगठन और पार्टी नेतृत्व ने उनका समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। नंदीग्राम में बीजेपी के प्रदर्शन को याद करते हुए रथ ने कहा कि जब उस निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मजबूत थी, तब

सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री को 1,956 वोटों से हराया था। रथ ने कहा कि अधिकारी 2026 के चुनावों में लगभग 10,000 वोटों से नंदीग्राम जीते। उन्होंने कहा कि अगर वे 2026 में दो सीटों से चुनाव न लड़ते और नंदीग्राम को ज़्यादा समय दे पाते, तो उनकी जीत का अंतर और भी ज़्यादा होता। रथ ने अपने बेटे चंद्रनाथ रथ से जुड़ी जांच के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और परिवार को मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। हसीरानी रथ के नॉमिनेशन से नंदीग्राम में बीजेपी के कैंपेन को एक भावनात्मक पहलू मिला है, वहीं रेजीनगर के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी की संगठन के स्तर पर अनुभवी नेता को प्राथमिकता देने की सोच को दिखाता है। नंदीग्राम उपचुनाव की ज़रूरत तब पड़ी जब अधिकारी, जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती थीं, ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने और नंदीग्राम सीट छोड़ने का फ़ैसला किया। नंदीग्राम में कई पार्टियों के बीच मुक़ाबला होने की उम्मीद है; यहाँ वोटिंग 6 अक्टूबर को होगी, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 16 सितंबर है और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके चंद्रनाथ रथ 6 मई को मध्यमग्राम में कार से जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर कथित तौर पर गोलीबारी की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की थी, जिसके बाद इसे ष्टक्चढ्ढ को सौंप दिया गया। नंदीग्राम में हसीरानी रथ की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

अमित शाह की मौजूदगी में किशाउ डैम पर छह राज्यों में समझौता

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में छह राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोंस नदी पर बनने वाली इस परियोजना से सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यह कदम यमुना नदी के पुनरुद्धार और बेसिन राज्यों की जल सुरक्षा को मजबूत करेगा। ऊपरी यमुना बेसिन में राज्यों के बीच सहयोग और जल संसाधनों के विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौते के ज्ञापन (रूश्व) पर हस्ताक्षर किए। इन छह राज्यों और केंद्र के बीच लगभग 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रेणुका जी और लखवार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स से जुड़े दो समझौते पहले ही हो चुके हैं

और इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पर हुआ समझौता, निर्माण के लिए छह राज्यों के बीच किया गया तीसरा समझौता है।

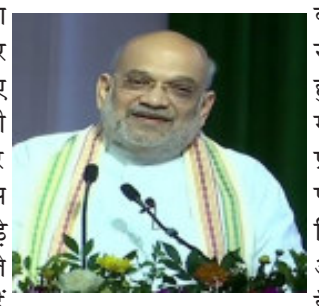

लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव और शामिल राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करना लंबे समय से अटके हुए %किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट% को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह समझौता सहकारी संघवाद की भावना और यमुना बेसिन के जल संसाधनों के टिकाऊ विकास और बेहतर इस्तेमाल के लिए केंद्र और बेसिन राज्यों की सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, टोंस नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में 232.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है, जिसकी लाइव स्टोरेज क्षमता 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर (स्ष्टरू) होगी। इससे लगभग 0.97 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और सालाना लगभग 1,476 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

जमा किए गए पानी से यमुना को पुनर्जीवित करने और पीने व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, खासकर राजस्थान और दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में, जिससे इस इलाके में जल सुरक्षा मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के जॉइंट वेंचर, किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा।

नवरात्र से पहले विशेष संसद सत्र की तैयारी! सरकार ने विपक्ष से किया संपर्क

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): जानकारी यह है कि संसद का सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, और केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों से संपर्क किया है। सरकार चाहती है कि त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ऑफिस ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क किया है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 11 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होने से पहले यह सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे के ऑफिस की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। संसद के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

करने (प्रोरोगेशन) में हुई असामान्य देरी के बीच यह कदम उठाया गया है, जिससे विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, हालांकि सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने दोनों सदनों के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने में सबसे लंबी देरी का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते रिजिजू के यह कहने के बाद कि संसद परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सत्र बुला सकती है, विशेष सत्र की चर्चा और तेज हो गई।

इसके बाद, खड़गे ने रिजिजू को पत्र लिखकर फिर से मांग की कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रस्तावित एजेंडे के बारे में जानकारी दे। 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार को एक झटका लगा, जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़ा परिसीमन वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया।

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की तैयारी पर आरोप, राहुल गांधी बोले-अमेरिकी दबाव में झुकी सरकार

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है और ''कॉम्प्रोमाइज्ड'' (समझौता कर चुके) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापार समझौते की तरह इस मामले में भी अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक यूपीआई लेनदेन की संख्या भले ही करीब पांच प्रतिशत हो, लेकिन यूपीआई के कुल लेनदेन मूल्य में इनकी हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है तथा उसका बोझ अंततः कीमतों में बढ़ोतरी के जरिये ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा। सरकार ने बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन या रुपे डेबिट कार्ड के जरिये किए गए भुगतान पर कोई शुल्क न लगाने का निर्देश दिया

है। सरकार ने हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया कि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लागू होगा या नहीं और इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा या नहीं। अभी तक किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने इसको लेकर 'एक्स' पर पोस्ट किया, '' सरकार का कहना है कि ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां लंबे समय से भारत की शून्य एमडीआर नीति का विरोध करती रही हैं और अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। गांधी ने कहा, ''अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरह ही, कॉम्प्रोमाइज्ड (समझौता कर चुके) प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने समर्पण कर रहे हैं।'' उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्राहक से सीधे शुल्क नहीं लिए जाने के बावजूद व्यापारी पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी यूपीआई शुल्क को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि सरकार ने ''यूपीआई पर कोई शुल्क नहीं'' की व्यवस्था को बदलकर दो हजार रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खरगे ने दावा किया कि पांच हजार रुपये के लेनदेन पर 25 रुपये और 10 हजार रुपये के लेनदेन पर 50 रुपये तक की संभावित वसूली की जा सकती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या यह वास्तव में प्रस्तावित है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि व्यापारियों पर एमडीआर (व्यापार रियायत दर) का अतिरिक्त बोझ डाला जाता है तो वह अंततः वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल होकर आम उपभोक्ता से ही वसूला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के बजाय सरकार उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर रही है। खरगे ने कहा, ''10 वर्ष पहले नोटबंदी को डिजिटल भुगतान और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपाय के तौर पर पेश किया गया था। ऐसे में अब यूपीआई पर शुल्क लगाने की संभावित व्यवस्था सरकार की उस नीति पर सवाल खड़े करती है।'' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले में सरकार से सवाल किया कि क्या यह कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र का रास्ता खोलने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। रमेश ने आरोप लगाया कि ''साफ तौर पर हम सभी से यूपीआई लेनदेन पर शुल्क वसूलने की जमीन तैयार की जा रही है।

विविध समाचार

पीएम आवास योजना पर रायपुर में भिड़े भुपेश बघेल और विजय शर्मा, आंकड़ों पर तकरार

मुंबई १५/०९ (संवाददाता): छज़ीसगढ़ के उपमुज़्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुज़्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मंगलवार को रायपुर प्रेस ज़्लब में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर खुली बहस हुई। दोनों नेताओं ने घरों की संज़्या, लक्ष्यों व केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका को लेकर एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि शर्मा द्वारा बघेल को इस मुद्दे पर आमने-सामने चर्चा की चुनौती दिए जाने के बाद यह बहस आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने अपने-अपने कार्यकाल के आंकड़े पेश किए। बहस मुज़्य रूप से स्वीकृत, लंबित और पूरे हो चुके घरों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की भूमिका पर केंद्रित रही। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ''झूठ'' बोल रही है और लोगों को गुमराह करने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभाल रहे शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकार पर लाखों गरीब परिवारों को घर उपलज़्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा, ''कांग्रेस ने गरीब लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया।'' उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11.51 लाख घर पूरे किए हैं और हाल में 3.65 लाख और घरों को मंजूरी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने 2021-22 में केंद्र द्वारा दिए गए 7.81 लाख घरों के लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया।

बघेल के 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास पोर्टल बंद रहने के दावे पर शर्मा ने उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया था ज़्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए धन मंजूर नहीं किया था। वहीं, बघेल ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए घरों का लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया था, जिसमें 18 लाख घर और 'आवास प्लस' श्रेणी के तहत आठ लाख अन्य घर शामिल थे। उन्होंने कहा कि 2015 में योजना शुरू होने से 2023 में उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक राज्य में करीब 11 लाख घर बनाए गए थे। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने सज़ा में आने के बाद 14 दिसंबर, 2023 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख घरों को मंजूरी देने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छज़ीसगढ़ के तीन दौरों में करीब 10 लाख और घरों की घोषणा की, जिससे कुल 28 लाख घरों का आंकड़ा सामने आया। शर्मा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय योजना के तहत घरों की मंजूरी केंद्र सरकार देती है। उन्होंने कहा कि 18 लाख का आंकड़ा घर बनाने के वादे से जुड़ा है, जिसमें 2016 से 2023 के बीच लंबित 2.46 लाख घर, स्थायी प्रतीक्षा सूची के तहत 6.99 लाख घर, 'आवास प्लस' के तहत 8.19 लाख घर और मुज़्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,090 घर शामिल हैं। उन्होंने दोहराया कि पिछले ढाई वर्षों में 11.51 लाख घर बनाकर पूरे किए गए हैं।

बहस के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस के बीच फिर जुबानी जंग शुरू हो गई। दोनों दलों ने बहस में अपनी जीत का दावा किया। बघेल ने 'एज़्स' पर शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा, ''अगली बार किसी समझदार को भेजना।

'छोटा रिचार्ज' रील के लिए ही ठीक है।'' भाजपा ने पलटवार करते हुए पोस्टर जारी किए और बघेल पर ''हवा-बाजी'' करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि सही आंकड़े सामने आने से ''भ्रम का गुज़्बारा फूट गया है।'' शर्मा ने बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बघेल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों की जानकारी नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि बघेल ने अपने कार्यकाल में ''गलत हुआ'' स्वीकार कर लिया है।

सुको ने राजपाल यादव को पांच करोड़ जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय देने के साथ लगाई फटकार

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): सुप्रीम कोर्ट ने एज़्टर राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में सरेंडर करने से मिली अंतरिम राहत को आगे बढ़ा दिया है, साथ ही उन्हें दो हफ़्ते के अंदर रजिस्ट्री में ?5 करोड़ जमा करने को कहा है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को कोर्ट ने यादव को सुरक्षा देते हुए एक दिन के अंदर यह रकम जमा करने को कहा था। मुज़्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब यादव और उनकी पत्नी की तरफ़ से दायर याचिकाओं का ज़िक्र श्क्र सौरभ त्रिवेदी ने मौखिक रूप से किया। बेंच ने यादव की ज़्यादा समय की मांग को अनिच्छा से मंज़ूरी दी और कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि वह ड्रामा और एज़्टिंग करने में माहिर हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के जुलाई के फ़ैसले को चुनौती देते हुए एक स्ल्क्ष (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की गई है। इस फ़ैसले में कोर्ट ने कई चेक बाउंस मामलों में बॉलीवुड एज़्टर की सज़ा को बरकरार रखा था, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में दखल देने से इनकार कर दिया था और प्रोबेशन की उनकी अपील को भी ठुकरा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि बार-बार वादे तोड़ने और न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करने की वजह से वह नरमी पाने के हकदार नहीं रहे। यह समझते हुए कि यादव आगे कानूनी उपाय अपना सकते हैं, हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ा के अमल से दो महीने की मोहलत दी थी ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव और अन्य लोगों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने %नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज़्ट% के तहत अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती दी थी। दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जिसे किसी एज़्टर की मर्ज़ी से दोबारा लिखा जा सके।

कोर्ट ने गौर किया कि बार-बार मौके मिलने के बावजूद, यादव शिकायतकर्ता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे और कोर्ट में दिए गए वचनों का भी बार-बार उल्लंघन किया।

प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि एज़्टर ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति बहुत कम सज़्मान दिखाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यादव के एक बयान पर भी ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता को पैसे देने के बजाय वे पांच बार और जेल जाना पसंद करेंगे। कोर्ट ने इस टिप्पणी को उनके व्यवहार और कानूनी दायित्वों को पूरा न करने की अनिच्छा का संकेत माना।

राहुल गांधी के आरोप झूठे, दो हजार से बड़े डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं-अठावले

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ज़्यादा कीमत वाले डिजिटल ट्रांजैक़्शन पर शुल्क लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ?2,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक़्शन पर कोई शुल्क लगाने का फ़ैसला नहीं किया है और इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया।

एएनआई से बात करते हुए अठावले ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे ट्रांजैक़्शन शुल्क शुरू किया जाए या बढ़ाया जाए।

अठावले ने एएनआई को बताया अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ट्रांजैक़्शन ?2,000 से ज़्यादा का होता है, तो सरकार उस पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। राहुल गांधी का यह आरोप झूठा है। अभी सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें इस तरह का कोई शुल्क शुरू करने या बढ़ाने की बात हो। अठावले ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा %ईज़् ऑफ़ डूइंग बिज़नेस% (कारोबार में आसानी) को प्राथमिकता दी है और वह व्यापारियों पर कोई बोझ नहीं डालेगी।

उन्होंने कहा, आगे चलकर सरकार जो भी फ़ैसला सही समझेगी, वह लेगी, लेकिन सरकार का रुख़ कभी भी व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान करने का नहीं रहा है। इस आरोप को खारिज करते हुए कि भारत के नीतिगत फ़ैसले विदेशी ताक़तों से प्रभावित होते हैं, अठावले ने ज़ोर देकर कहा कि मोदी सरकार बाहरी दबाव में काम नहीं करती है और दुनिया भर में स्वतंत्र व संतुलित द्विपक्षीय संबंध बनाए रखती है।

अठावले ने कहा, इसके अलावा, सरकार पर अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार चीन, रूस, ईरान और सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती है। अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। इसलिए, नरेंद्र मोदी और हमारी भारतीय सरकार पर निश्चित रूप से अमेरिका का कोई दबाव नहीं है।

उमर खालिद को बीके हरिप्रसाद ने बताया राष्ट्रवादी, एबीवीपी के विरोध पर खड़े किये सवाल

नयी दिल्ली १५/०९ (संवाददाता): कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद ने जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को मंगलवार को एक राष्ट्रवादी बताया। हरिप्रसाद ने कहा कि खालिद पर बनी वृज़ाचित्र फिल्म की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को जेल में बंद नेता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सितंबर 2020 में गिरज़्तार किए गए खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के ''मुज़्य साजिशकर्ताओं'' में से एक होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हरिप्रसाद ने पत्रकारों से कहा, ''उमर खालिद एक राष्ट्रवादी हैं। एबीवीपी को खालिद के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ज़्योंकि एबीवीपी नाथूराम गोडसे को पूजती है, जो राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी था- देश का पहला आतंकवादी।खालिद के बारे में बोलने का उनका कोई नैतिक अधिकार या नैतिक आधार नहीं है।'' हरिप्रसाद एनएलएसआईयू परिसर में खालिद पर बनी वृज़ाचित्र फिल्म की स्क्रीनिंग का एबीवीपी द्वारा विरोध किए जाने संबंधी सवाल का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध छात्र संगठन एबीवीपी ने कहा कि इसने ''कांग्रेस नेता के बौद्धिक दिवालियापन को उजागर कर दिया है।'' भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने के मुद्दे पर हरिप्रसाद ने सवाल किया कि ज़्या भाजपा ने गोवा और पूर्वोज़र में इसे लागू किया है? उन्होंने सवाल किया, ''यूसीसी लाने का ज़्या मतलब है?ज़्या वे (भाजपा) यह गोवा में लाये हैं? ज़्या वहां इसे लागू किया गया है?'' हरिप्रसाद ने कहा कि धर्म के लिहाज से पूर्वोज़र पूरी तरह अलग है। उन्होंने कहा, ''दक्षिण और उज़र में कोई एकरूपता नहीं है।

इसलिए वे इस देश के लोगों पर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं कर सकते।'' मुज़्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर हरिप्रसाद ने कहा कि मुज़्यमंत्री इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हरिप्रसाद पर निशाना साधते हुए एबीवीपी ने एक बयान में कहा, ''कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कैसे बता सकती है, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हुए हिंसक हमले के मुज़्य साजिशकर्ता और दोषी आतंकवादी अफजल गुरु का खुले तौर पर समर्थन और उसका महिमामंडन किया था, जिसमें हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का खून बहा था।''

उसने सवाल किया, ''अगर हरिप्रसाद की नजर में खालिद राष्ट्रवादी है, तो ज़्या कांग्रेस पार्टी अफजल गुरु के सज़्मान और महिमामंडन में कार्यक्रम आयोजित करने वालों का समर्थन करती है?'' एबीवीपी ने यह भी सवाल किया कि ज़्या कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने ''भारत तेरे टुकड़े होंगे'' का नारा लगाया था। एबीवीपी के बेंगलुरु शहर अध्यक्ष अभिनंदन मिर्जी ने कहा, ''ज़्या कांग्रेस जेएनयू में लगाए गए हिंसक भारत-विरोधी नारों और 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान जानबूझकर की गई उस उकसावे की कार्रवाई का समर्थन करती है, जिसके कारण खून-खराबा हुआ?

बिहार पुलिस एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग पर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस में झड़प

पटना १५/०९ (संवाददाता): मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में कॉज़्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बड़ी संज़्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। वे हाल ही में हुई बिहार पुलिस सब-इंस्पेज़्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने और कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रदर्शन गांधी मैदान के पास शुरू हुआ और जेपी गोलंबर के पास और तेज़ हो गया, जहाँ प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की भी खबर है। छात्र खास तौर पर सब-इंस्पेज़्टर के 1,799 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को लेकर नाराज़ हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए और इसे पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए।

विरोध कर रहे उज़्मीदवारों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उज़्मीदवारों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता की मांग की। छात्रों का आरोप था कि 1,799 दारोगा पदों के लिए हाल ही में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए और एक पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए इसे दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि नई परीक्षा से उनकी चिंताओं का समाधान होगा और यह सुनिश्चित होगा कि सभी उज़्मीदवारों को समान अवसर मिले। बिहार पुलिस स्ब्ढ परीक्षा के अलावा, प्रदर्शनकारियों ने बिहार लोक सेवा आयोग (ङ्क्क्स्ष्ट) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की। प्राथमिकऔर माध्यमिक विद्यालय (च-12)

अपने विरोध प्रदर्शन के तहत सड़कों पर उतरने से पहले, कई छात्र संगठनों की अगुवाई में बड़ी संज़्या में छात्र जेपी गोलंबर के पास जमा हुए। प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर और रामगुलाम चौक के बीच मुज़्य सड़क को जाम कर दिया।

सड़क जाम होने से इलाके में ट्रैफिक पर असर पड़ा और आने-जाने वालों व पैदल चलने वालों को परेशानी हुई। इस विरोध प्रदर्शन का असर अशोक राजपथ और आसपास के इलाकों की दूसरी मुज़्य सड़कों पर भी पड़ा। प्रदर्शन कर रहे उज़्मीदवारों ने घोषणा की है कि वे बिहार दारोगा मुज़्य परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मुज़्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और उसका घेराव करेंगे।

पटना में कई छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। गांधी मैदान में हालिया प्रदर्शन, भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे उज़्मीदवारों के बढ़ते आंदोलन का ही एक हिस्सा है।

विविध समाचार

मॉनसून सीजन में ऐसा रहे आपका स्टाइल स्टेटमेंट

अपने बॉटम्स को चुनते वक्त बेहद सावधानी रखें। फ़ेमिनिन स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी चुने जा सकते हैं बजाए किसी फुल लेंथ आउटफिट के। पूरी तरह से सफ़ेद को अपनाना रिस्की हो सकता है।

बड़े या ग्राफिक प्रिंट को कपड़ों पर जगह दें। ट्रॉपिकल प्रिंट्स, पोल्का डॉट्स और फ्लोरल डिजाइन भी सफ़ेद के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है।

पूरी तरह सफ़ेद शॉर्ट ड्रेस को बॉम्बर, डेनिम जैकेट या ट्रेंच कोट के साथ टीम करें। इससे आपकी ड्रेस बारिश के दागों से तो बची ही रहेगी, और इससे आपको लेयर्स के साथ खेलने की आजादी भी मिलती है। आप लेस वाली ड्रेस भी चुन सकते हैं या लेस लगा सकते हैं। किसी भी हल्के रंग की ड्रेस पर सफ़ेद लेस लगाकर भी बात बन सकती है। सफ़ेद जैसे रंग भी चलन में हैं। जैसे बैज, ब्लश, ऑफ वाइट और क्रीम भी पहना जा सकता है।

ईयरफोन्स का इस्तेमाल है खतरनाक, हो जाइए सावधान

बड़ों से लेकर बच्चों तक के कानों में आपने ईयरफोन्स लगे तो देखा ही होगा। तेज़ आवाज में गाने सुनना, टी.वी देखना कई बच्चों की आदत बन चुका है। इसके चलते वे टिनीटिस (कान में लगातार गूंजती आवाज) की समस्या से जूझ रहे हैं। यह बहरेपन का लक्षण होता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि इन लक्षणों को प्रारंभिक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इनका सामना कर रहे युवाओं को बहरेपन का गंभीर खतरा है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि टिनीटिस की समस्या, ईयर बड है, जिनका इस्तेमाल युवा संगीत सुनने के लिए हर रोज़ लंबे समय तक करते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि नाइट क्लब, डिस्को और रॉक कंसर्ट जैसे शोर शराबे वाले स्थानों पर जाना भी कान की सेहत के लिए नुकसानदायक है।

टिनीटिस बीमारी के लक्षण

टिनीटिस, एक ऐसी मेडिकल समस्या है, जिसमें कान में लगातार ऐसी आवाज बजती रहती है। इसका कोई बाहरी स्रोत मौजूद नहीं होता है। इससे पीड़ित लोग कानों में लगातार घंटी बजने जैसी आवाज की शिकायत करते हैं। कई तो कान में सीटी बजने, गूंज, फुफकार या चींची की सी आवाज बताते हैं।

ब्राजील की साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के तनित गांज सानेचेज ने बताया कि ह्यकिशोरों में बड़े पैमाने पर टिनीटिस की समस्या है। इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इन युवाओं पर बहरेपन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर छोटे बच्चे लगातार उच्च स्तर पर होने वाले शोर के बीच रहेंगे, तो संभव है कि जब तक वे 30 या 40 साल की उम्र के होंगे तब तक उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी होगाह्ण। शोधकर्ताओं ने इसे साबित करने के लिए करीब 11 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों के कानों का परीक्षण करने के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया था।

इस दौरान किशोरों से एक प्रश्नावली भरने को कहा गया, जिसमें पूछा गया था कि क्या बीते 12 महीनों में उन्होंने टिनीटिस का

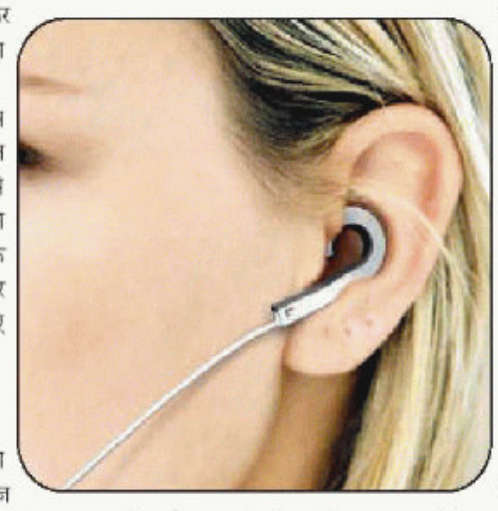

अनुभव किया है। अगर हां, तो उसकी आवाज कितनी तेज़ थी, कितनी देर तक सुनाई दी और बारंबारता कितनी है। लगभग आधे यानी 54.7 फीसदी बच्चों ने टिनीटिस का अनुभव किया।

हैरान कर देने वाले हैं निष्कर्ष

सानचेज ने कहा कि ह्यटिनीटिस की समस्या का इतने बड़े पैमाने पर पाया जाना खतरनाक है। माना जाता था कि टिनीटिस उम्रदराज लोगों को होने वाली समस्या है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब यह बच्चों और युवाओं को भी हो रही है, क्योंकि इन लोगों का शोर से ज़्यादा सामना होता है। इसके अलावा कुछ और कारक भी इस समस्या के जिम्मेदार हैं।

टिनीटिस की परेशानी का अनुभव कर चुके बच्चों की सुनने की क्षमता का आंकलन करने के लिए उन पर सायकोअकाउस्टिक परीक्षण किया गया। इसमें अकाउस्टिक चैंबर में ऑडियोलॉजिस्ट ने ऑडियोमीटर का इस्तेमाल कर सुनने की क्षमता की सीमा को मापा। इसके अलावा शोर से होने वाली परेशानी और टिनीटिस की समस्या को भी मापा गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि सायकोअकाउस्टिक परीक्षण के दौरान करीब 170 बच्चों में से 49 बच्चों को अकाउस्टिक बूथ में टिनीटिस की परेशानी महसूस हुई।

साउंड बूथ में टिनीटिस की जो सायकोअकाउस्टिक लक्षण मिले, वे वयस्कों में टिनीटिस की लंबे समय से चली आ रही समस्या की तरह ही हैं। सानचेज ने कहा कि ह्यहमने देखा है कि किशोरों को आमतौर पर टिनीटिस की समस्या होती है। लेकिन वयस्कों की तरह वे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं और इसके बारे में अपने अभिभावकों और शिक्षकों से शिकायत नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं और इस तरह यह समस्या लंबे समय तक चलती रहती है।

साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित इस शोध में शोधकर्ताओं ने बताया है कि शोध में शामिल बच्चों में ईयर बड का लगातार इस्तेमाल, शोर-शराबे वाले माहौल में ज़्यादा समय तक रहने जैसी जोखिम भरी आदतें होने के बावजूद, जिन्होंने टिनीटिस की समस्या का अनुभव किया, वे तेज़ आवाज़ को सहन नहीं कर सके।

फोर्ट जाधवगढ़ : विलासिता और पारंपारिकता का अद्भुत संगम

मध्यप्रदेश से लगे महाराष्ट्र में कई ऐतिहासिक अनुभव छुपे हैं जिन्हें एक बार तो आजमाना बनता है। ऐसी जगहों की लंबी लिस्ट में एक चमकता नाम है फोर्ट जाधवगढ़ का। इस किले की कमियों को दूर करके इसे महाराष्ट्र की पहली हेरिटेज होटल बनाया गया था। यह किला पुणे के पास है, यानी इंदौर से लगभग 600 किलोमीटर दूर। यह सफर आसानी से दिनभर में कार से ही तय किया जा सकता है।

मुंबई से यह सफर लगभग चार घंटे का है। 25 एकड में फैली इस प्रॉपर्टी में तमाम सुख-सुविधाएं मौजूद है और यहां चैन के कुछ दिन बिताए जा सकते हैं। इसे तैयार भी इस तरह से किया गया है कि आऊटडोर एक्टिविटीज, डेस्टिनेशन वेडिंग और परफॉर्मेंसेस के लिए यह आदर्श ठिकाना साबित होता है।

शाही स्वागत : फोर्ट में जब आप पहुंचते हैं तो ऐसे स्वागत होता है जैसे कोई मराठा किंग जंग जीतकर लौटा हो। तुतरी की आवाजें आपके कान में दूर से ही आने लग जाती हैं। ट्रेडिशनली तैयार महिलाएं तिलक करती हैं और आपको आपकी जगह तक लेकर जाती हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि यह किला नए जमाने की विलासिता और पारंपारिकता का अद्भुत संगम है। यहां आपको टच स्क्रिन स्विचेस भी दिख

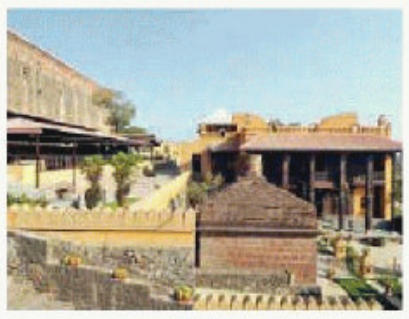

चेकलिस्ट

- साइट को साफ रखने में मदद करें।
- सूर्यास्त के बाद किले से बाहर अकेले नहीं जाएं।
- ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं।
- जंगल घूमने जाते वक्त बरसाती जरूर साथ रखें।
- किले से बाहर जाते वक्त होटल गाइड की सुविधा का फायदा उठाएं।

जाएंगे और पथरिले गलियारे भी। मराठी लिबास पहने मौजूद स्टाफ के अलावा वाय-फाय कनेक्टिविटी, लक्जरी स्पा और भी तमाम सुविधाएं यहां मिल जाएंगी। यह किला 1710 में बना था। वक्त के साथ यह नक्शे से भी गायब हो गया लेकिन 2007 में इसे यह नया रंग रूप दिया गया।

लक्जरी : इस किले में पचास से ज्यादा कमरे मौजूद हैं। इनमें सिग्नेचर सुईट, डिलक्स रूम, रॉयल टेंट्स और नीम कॉटेजेस शामिल हैं। तीन सौ साल पुरानी जलकुंभी अब स्वीमिंग पूल का रूप ले चुकी है। पूल से लगा स्पा में आप रिलेक्सिंग वेलनेस ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। बड़ी-बड़ी बालकनियां अब ऑलडे कॉफी शॉप में तब्दील हो गई हैं।

इसका नाम 'छज्जा'' रखा गया है। यहां का नजारा आपकी कॉफी की हर सिप के मजे को दोगुना करने का दम रखता है। खाने के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं और यहां हर तरह की चीजें मौजूद हैं। देसी और पारंपरिक खाने की तो बात ही निराली है।

इतिहास दर्शन : यहां पर एक 'इन हाउस'' म्यूजियम भी है। इसका नाम 'आई'' रखा गया है जिसका मराठी में मतलब 'मां'' होता है। यहां आपको ऐतिहासिक महत्व की पुरानी घरेलू चीजें देखने को मिल जाएंगी। कुछ तो लगभग 300 साल पुरानी हैं। इससे अलग एक बड़ी-सी प्लेट भी आपका ध्यान गरूर खींचेगी। इसे 'एलिफेंट्स प्लेट'' कहा जाता है क्योंकि राजा अपने प्रिय हाथी को खाना इसी पत्थर की भव्य प्लेट पर खिलाया करते थे।

लो ब्लड प्रेशर में लाभकारी तुलसी का पत्ता

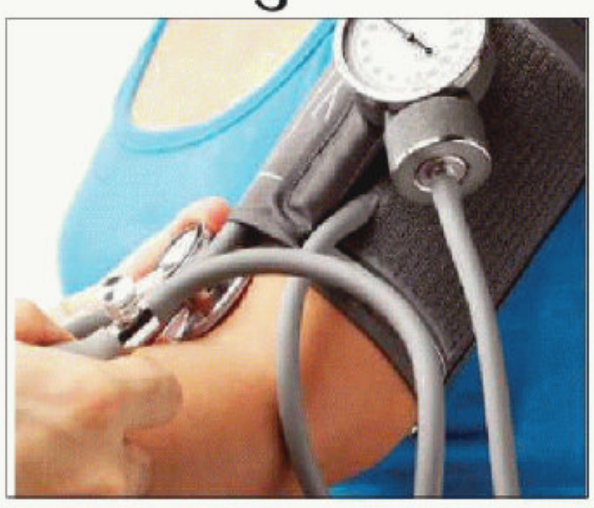

आजकल लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत बढ़ गई है। इसे गंभीरता से लेना जरूरी है नहीं तो इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ सकता है। ऐसे में दिल, किडनी, फ़ेफड़े और दिमाग पर इसका असर पड़ सकता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तुरंत करें ये काम।

नमक का पानी : नमक का पानी पीने से लो ब्लड प्रेशर में बहुत आराम मिलता है। इससे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। नमक में सोडियम मौजूद होता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हालांकि नमक की मात्रा इतनी भी न हो कि इससे शरीर पर बुरा असर पड़े।

कॉफी : लो ब्लड प्रेशर में कॉफी बड़े काम की चीज है। ब्लड प्रेशर कम होने पर स्ट्रांग कॉफी पीएं। ये तुरंत असर रता है। इसके अलावा हॉट चॉकलेट, कोला और कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है।

किशमिश : लो ब्लड प्रेशर में किशमिश भी बहुत फायदेमंद है। रात को पानी में कुछ किशमिश भिगो दें और उसे सुबह खाली पेट खा लें। इसके अलावा आप उस पानी को भी पी सकते हैं जिसमें किशमिश भिगोई गई थी।

तुलसी : तुलसी लो ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मददगार होती है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को संतुलित करता है और तनाव को भी दूर करता है।

फाइबरयुक्त भोजन के इन फायदों के सामने आने के बाद, डाइट में इनका शामिल होना और भी महत्वपूर्ण हो गया है

बढ़ती उम्र में लाभदायक फाइबर का सेवन

पाचन से लेकर त्वचा की चमक तक अक्सर विशेषज्ञ फाइबर्स के सेवन की सलाह देते हैं। अब एक शोध कह रहा है कि लंबे समय तक फ़ाइबर-रिच डाइट लेने से बढ़ती उम्र के साथ भी स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। जानें कैसे?

किसी भी व्यक्ति के लिए उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है। इसके साथ ही शरीर के अंगों का कमजोर होना और सफ़ेद बालों, झुर्रियों आदि के साथ बढ़ती उम्र का दिखाई देने लगना भी स्वाभाविक है लेकिन यदि प्रारंभ से प्रयास किए जाएं, तो बढ़ती उम्र के इन लक्षणों को लंबे समय तक टाला जा सकता है और उम्र संबंधी तकलीफों के असर को कम किया जा सकता है। भोजन भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोध ने किया खुलासा : इस संदर्भ में न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुए एक शोध ने यह साबित किया कि फाइबर से भरपूर भोजन, जोकि असल में कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है, और जिसे शरीर पचा नहीं सकता, वह असल में बढ़ती उम्र में स्वस्थ रखकर हमें फायदा पहुंचाता है। स्वस्थ रहकर उम्रदराज होने और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने के बीच की इस कड़ी को शोधकर्ताओं ने लाभकारी माना है। शोधकर्ता कहते हैं कि फाइबर्स की बदौलत, उम्र बढ़ने के साथ आने वाली मुश्किलों जैसे डिसेबिलिटी, डिप्रेशन के लक्षण, दिमागी अक्षमताओं, श्वास संबंधी तकलीफों से लेकर कैंसर और कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसी गंभीर अवस्थाओं तक से बचाव हो सकता है।

*** रोज की डाइट का हिस्सा :** शोधकर्ता कहते हैं कि रोजाना के भोजन का हिस्सा बनने वाले जो फाइबर शरीर पचा नहीं पाता, वे अधिकांशतः पौधों का ही भाग होते हैं, जैसे फल, सब्जियां और अनाज। ये फाइबर घुलनशील यानी सॉल्युबल और अघुलनशील यानी इन्सॉल्युबल, दो प्रकार के होते हैं। सॉल्युबल फाइबर पानी को सोखकर एक जैल जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह पाचन की क्रिया को धीमा कर देते हैं। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि इनसे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है जिससे हृदय रोग से बचने में मदद मिल सकती है। इस तरह के फाइबर्स के स्रोत हैं:

- ओट का चोकर
- बार्ले
- नट्स
- सीड्स
- चौला आदि बीन्स
- मटर जैसे दाने
- दाल आदि।

इन्सॉल्युबल फाइबर्स जल्दी से पेट भरने का काम करते हैं, जिससे आप भोजन की अधिक मात्रा ग्रहण करने से बच जाते हैं। ये गेहूं के आटे के चोकर, सबूत अनाज और सब्जियों में पाए जाते हैं।

शुरु से दें ध्यान

फाइबरयुक्त भोजन के इन फायदों के सामने आने के बाद, डाइट में इनका शामिल होना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि अक्सर विशेषज्ञ बचपन से ही इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। कई बार बच्चों में इसकी कमी गंभीर कब्ज का कारण भी बन जाती है। फाइबर्स का होना पाचन को दुरुस्त बनाता है और इस बात के तो स्पष्ट प्रमाण हैं ही कि पेट का अच्छी तरह साफ होना, पाचन का सुदृढ़ होना, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसलिए फाइबर्स से दोस्ती करना आवश्यक है।

रेसिपी

लाजवाब आलमंड कुकीज

सामग्री

2 कप मैदा, आधा कप बेसन, 1 कप चीनी, बेकिंग पावडर-आधा छोटा चम्मच, मक्खन-गूंथने के लिए, (इच्छानुसार) बादाम की कतरन।

विधि

पहले मैदा, बेसन, बेकिंग पावडर मिलाकर 3-4 बार छानें। इसमें मक्खन मिलाकर गूंथ लें। बादाम की कतरन भी मिला लें। इसमें इतना मक्खन मिलाएं कि पेड़े जैसा बन जाए।

अब इससे मनचाहे आकार की कुकीज़ बना लें और प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-20 मिनट रखें। लीजिए तैयार बेक्ड कुकीज़ निकालें और क्रिसमस के स्पेशल पर्व पर पेश करें।

चटपटे वेजीटेबल चीज नूडल्स

सामग्री

250 ग्राम नूडल्स (उबले हुए), 2 गाजर (बारीक कटे हुए), 1 टमाटर, 2 प्याज लंबे कटे, 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च (बारीक कटी), अदरक एक छोटा टुकड़ा, एक कटोरी लंबी कटी बींस, 2 आलू (कटे हुए), 50 ग्राम चीज, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, चीली सॉस, टमाटर सॉस, 2 चम्मच जीरा, तेल (आवश्यकतानुसार)।

विधि

सर्वप्रथम कड़ाही में तेल गरम करके जीरा, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, बींस डालें और पांच-दस मिनट तक पका लें। फिर टमाटर और नमक डालकर ढंक कर फ्राय करें।

अब उसमें नूडल्स डालकर ऊपर से सोया सॉस, चीली सॉस और टोमेटो सॉस डालें और हिलाएं। तत्पश्चात चीज को किसकर तैयार नूडल्स में ऊपर से डालें और हरा धनिया से सजा कर पेश करें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

संसद में खतरनाक खेल की शुरुआत

देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल को भाजपा अब एक खतरनाक स्तर पर ले आई है। इसे रोकना या इसका हल निकालना आसान नहीं है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण हिंदू या मुसलमान बोलकर नहीं हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। इस खेल में इतिहास को बदला जा रहा है, तथ्यों पर झूठ चढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह सब संस्थागत तरीके से हो रहा है। सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा करना इसी का प्रमाण है। इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा है, जिसमें कामकाज के कुछ घंटे पहले ही हंगामे में निकल चुके हैं। बचे वक्त का अच्छा इस्तेमाल देश के सामने आई बड़ी विपदाओं पर चर्चा कर उनका हल निकालने या विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर विमर्श करने में लगाया जा सकता था। एसआईआर के कारण बीएलओज़ की मौत, इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्रियों पर आई मुसीबत, दिल्ली में आतंकी हमला, प्रदूषण, रुपए की गिरती कीमत, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पेंच, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान–मजदूर हित, युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिन पर संसद का कीमती वक्त लगना चाहिए था। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेढ़ सौ साल पहले लिखे गीत को लेकर अकारण बहसबाजी की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यह दुस्साहस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में देश को उन ताकतों से मुक्त करना है, जिनके कारण संविधान बना हुआ है। यह संविधान ही है जो देश में तानाशाही कायम नहीं होने देता। लोगों को हि मत देता है कि अगर उन्हें सरकार का कोई फैसला पसंद न आए या अपने हित खतरे में पड़ते दिखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी संविधान की दी हुई ताकत से किसानों ने एक साल लंबा आंदोलन चलाया, जिसके बाद नरेन्द्र मोदी को कृषि कानून वापस लेने पड़े। अभी संचार साथी ऐप प्रीइंस्टाल करने का फैसला हटाना पड़ा। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें बहुमत के बावजूद मोदी सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। यही बात शायद सरकार को खटक रही है, क्योंकि इस बार तो संसद में विपक्ष पहले से अधिक ताकतवर है। ऊपर से बिहार चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए अब नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम् का विवाद खड़ा कर कांग्रेस को निशाने पर लेने की एक और कोशिश की है। संसद में श्री मोदी के भाषण से यह समझ आ गया कि चर्चा शब्द का मुखौटा लगाकर भाजपा देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रही है, ठीक ऐसा ही काम भाजपा के पुरखों यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने किया था। आजादी की लड़ाई के लंबे कालखंड में संघ का योगदान रत्ती भर भी देखने नहीं मिलता है। बल्कि इस बात के सबूत हैं कि वी डी सावरकर ने सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी और उनकी सेवा करने का वचन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भी संघ के लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे और जनता को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन आज उसी संघ से निकले नरेन्द्र मोदी कांग्रेस पर देश विभाजन का आरोप लगा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोह मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम् के खिलाफ नारा बुलंद किया था। इसको लेकर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् के 100 साल हुए थे, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। लगभग एक घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने 13 बार कांग्रेस और 7 बार नेहरू का नाम लिया। श्री मोदी ने पं.नेहरू को मुस्लिम लीग के आगे झुकता बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि 1937 में ब्रिटिश इंडिया में कुल 11 राज्य थे, तब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार बनाई।

मुश्किल मुद्दों की वजह से मणिपुर समस्या के समाधान में हो रही है देरी

रवींद्र नाथ सिन्हा

मणिपुर का पूरा इलाका–पहाड़ियां और घाटियां दोनों–हमेशा मणिपुर के राजाओं, राज्य दरबार और बाद में, राज्य सरकार के प्रशासन में था। मैनेजमेंट के नियमों (1907) ने साफ तौर पर दरबार को दोनों इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया, जो ज़मीन, जंगल और टैक्स का प्रबंधन करता था। ब्रिटिश अधिकारी नियमित तौर पर यह रिकॉर्ड करते थे कि जंगल और इलाके महाराजा की संपदा थे। हालात के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया, जो बदलते रहते हैं, ने मणिपुर में बदलते घटनाक्रम में जातीय संघर्ष की कहानी को अलग करते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 6 और 7 नवंबर को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के दायरे में आने वाले 24 विद्रोही गुटों में दो बड़े गुट हैं। दो दिनों तक चली बातचीत को केन्द्रीय गृह मंत्रालय और एक तरह से पहचाने जाने वाले% 24 कुकी–ज़ो विद्रोही गुटों के बीच एक अहम बातचीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली 4 सितंबर को जो बातचीत हुई थी, उसके बाद बंद पड़े एसओओ को फिर से सक्रिय किया गया था, जिससे मैतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन (सीएसओ संगठन) बहुत नाराज़ थे, जो एसओओ की उस अवधारणा के ही खिलाफ हैं जिसे 2008 में लाया गया था।

फिर से एसओओ को सक्रिय करने के समझौते में नई शर्तें हैं, जिनमें संविधान के अंदर समझौता, इलाके की अखंडता का भरोसा, कैडर की जांच और पुष्टि, विदेशी नागरिकों को वापस उनके देशों में भेजना और शिविरों को फिर से अन्यत्र ले जाना शामिल हैं। एसओओ में पहले से तय समय पर और आगे बढ़ाने का प्रावधान था। हालांकि, 29 फरवरी, 2024 को, यानी 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के 10 महीने बाद और जब मणिपुर की कानून–व्यवस्था की हालत सबसे खराब थी, तब के मु यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने तीन–तरफ़ा एसओओ से यह कहते हुए बाहर निकलने का फैसला किया कि इसके दायरे में आने वाले ग्रुप ज़मीनी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

यह बताना ज़रूरी है कि 3 मई, 2023 से पहले, ये ग्रुप संविधान के छठे शेड्यूल के तहत स्वायत्त क्षेत्र परिषद (ऑटोनॉमसटेरिटोरियल काउंसिल) की मांग कर रहे थे। हिंसा बढ़ने और बेघर हुए लोगों की सं या बढ़ने के बाद, उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लिए विधायिका से केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठानी शुरू कर दी। जैसा कि इस लेख के शुरू में ही बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया मणिपुर आ यान के हिस्से हैं। अब मैतेई सीएसओ की बारी थी कि वे प्रतिक्रिया करें और पिछली ज़मीनी हकीकत का अपना संस्करण पेश करें और उसके समर्थन में ऐतिहासिक काल खंडों, संबंधित नियम और न्यायालयों के फैसले% का हवाला दें। 17 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री को लिखे एक ज्ञापन में, जिसकी प्रतिलिपियां केंद्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सलाहकार (नॉर्थ–ईस्ट) ए के मिश्रा को भी भेजी गई हैं, मणिपुर एकता और अखंडता पर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (कोकोमी) ने कहा है= यह कहना कि मणिपुर के पहाड़ी इलाके कभी भी मणिपुर के महाराजा के शासन में नहीं थे, ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को जानबूझ कर गलत तरीके से पेश करना है% जिसका मकसद एक अलग कुकी प्रशासनिक क्षेत्र की मांग को सही ठहराना है। इसके उलट, पुराने रिकॉर्ड, मणिपुर स्टेट दरबार रूल्स (1907) और आज़ादी के बाद अदालतों के फैसले (जो 1963 और 1979 में आये थे) ने इस बात की पुष्टि की कि पूरा इलाका, जिसमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं, राज्य

यह एक सोच–समझकर बनाई गई ब्रिटिश औपनिवेशिक सीमावर्ती नीति (कॉलोनियल फ्रंटियर स्ट्रैटेजी) का नतीजा था, जिसे अस्थिर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस भूराजनीतिक इंजीनियरिंग में एक अहम भूमिका मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट (1844–1863) लेि टनेंट–कर्नल विलियम मैकुलोच ने निभाई थी। बसाया गया जो धीरे–धीरे गांव बन गए। इन तीन मकसदों को पूरा करने के लिए ये इलाके बनाए गए थे– लुशाई पहाड़ियों से होने वाले हमलों के खिलाफ एक ह्यूमन बफ़र ज़ोन बनाना, ज़मीन को राजस्व कमाने वाली खेती के इस्तेमाल के तहत लाना और लोगों को मज़दूरी और सहायक सेना के स्रोत के तौर पर काम पर रखना।

और उसके बाद आने वाले शासकों के लगातार कानूनी अधिकार क्षेत्र में रहा।

कुकी ग्रुप के पुरखों के ज़मीन के हक के दावे को पुरानी समय–सीमा और उनके बसने के तरीके से चुनौती मिलती है, जो मु य रूप से औपनिवेशिक दौर की बात थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान बसने की नीति के तहत, पहले एंग्लो–बर्मी युद्ध (1824–1826) में ब्रिटिश जीत के बाद लगभग 1840 में पहाड़ी इलाकों में कुकी प्रव्रजन शुरू हुआ। यह एक सोच–समझकर बनाई गई ब्रिटिश औपनिवेशिक सीमावर्ती नीति (कॉलोनियल फ्रंटियर स्ट्रैटेजी) का नतीजा था, जिसे अस्थिर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस भूराजनीतिक इंजीनियरिंग में एक अहम भूमिका मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट (1844–1863) लेि टनेंट–कर्नल विलियम मैकुलोच ने निभाई थी।

कुकी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से उन इलाकों में बसाया गया जो धीरे–धीरे गांव बन गए। इन तीन मकसदों को पूरा करने के लिए ये इलाके बनाए गए थे– लुशाई पहाड़ियों से होने वाले हमलों के खिलाफ एक ह्यूमन बफ़र ज़ोन बनाना, ज़मीन को राजस्व कमाने वाली खेती के इस्तेमाल के तहत लाना और लोगों को मज़दूरी और सहायक सेना के स्रोत के तौर पर काम पर रखना। 19वीं सदी के बीच की यह घटना, कोकोमी के कन्वीनरखुरैजमअथौबा के हस्ताक्षरित किए हुए प्रधानमंत्री को भेजे मांगपत्र में बताया गया है कि यह घटना %एक हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से मैतेई और दूसरे आदिवासी पहाड़ी समुदायों के लगातार और अच्छी तरह से रहने% के दस्तावेज से बिल्कुल अलग है। अथौबा ने यह भी कहा है कि कुकी शब्द एक औपनिवेशिक बनावट है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए चिन–लुशाई पहाड़ियों और आस–पास के इलाकों में रहने वाले अलग–अलग तरह के कबीलों के के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया था।

मणिपुर का पूरा इलाका–पहाड़ियां और घाटियां दोनों–हमेशा मणिपुर के राजाओं, राज्य दरबार और बाद में, राज्य सरकार के प्रशासन में था। मैनेजमेंट के नियमों (1907) ने साफ तौर पर दरबार को दोनों इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया, जो ज़मीन, जंगल और टैक्स का प्रबंधन करता था। ब्रिटिश अधिकारी नियमित तौर पर यह रिकॉर्ड करते थे कि जंगल और इलाके महाराजा की संपदा थे। मणिपुर के भारत में शामिल होने पर, ऐसी सभी ज़मीनों का मालिकाना हक कानूनी तौर पर राज्य सरकार के पास आ गया। इस निरंतरता को भारत के संविधान की धारा 372, पार्ट सी स्टेट्स लॉज़ एक्ट (1949) और मर्ज्ड स्टेट्स लॉज़ एक्ट (194) ने सुरक्षित रखा। मणिपुर उच्च न्यायालय (1963) और गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1979) ने कानूनी ढांचे को सही ठहराया था। इसलिए, केंद्र सरकार को कुकी लोगों के स्वदेशी होने और पुरखों के ज़मीन के अधिकारों के दावों को खारिज कर देना चाहिए, जो ऐतिहासिक नहीं% हैं और मणिपुर राज्य की कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के खिलाफ हैं। कोकोमी ने तर्क दिया है कि उनकी मांग मानना राज्य के मूल निवासियों की क्षेत्रीय अखंडता और कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करने जैसा होगा।

मोदी को उलटा पड़ा वंदे मातरम् पर बहस का दांव

अनिल जैन

लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से मोदी और उनकी पार्टी को यह भी बताया कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पांच लोगों की एक समिति ने लिया था जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद शामिल थे। राष्ट्रीय गीत %वंदे मातर % की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार की पहल पर संसद के दोनों सदनों में एक–एक दिन की विशेष बहस का आयोजन हुआ। सब जानते हैं कि यह गीत हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान रचा गया था और यह देश भर में, खासकर बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के अधिवेशनों में भी यह गीत गाया जाता था और देश आजाद होने के बाद इसे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में भी मान्यता दी। इसलिए इस पर चर्चा बहस करने–कराने का कोई औचित्य नहीं था। हां, इसके 150 वर्ष पूरे होने पर संसदीय बहस से इतर कोई कार्यक्रम जरूर हो सकता था, लेकिन सरकार का मकसद इस पर बहस के जरिये राजनीतिक लक्ष्य को साधना था, सो उसने तमाम ज्वलंत और जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर वंदे मातरम् पर बहस कराई।

देश में पिछले कुछ दिनों से कई तरह के विवादों से घिरे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते अब तक 45 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ सहित 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की दुर्दशा के रोज नये रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली सहित समूचा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण की मार से गैस चैंबर बना हुआ है, जिससे लाखों लोगों के फेफड़े सड़ गए हैं। देश के तमाम हवाई अड्डों पर पांच दिन तक अफरा–तफरी मची रही और लाखों लोग परेशान हुए। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जल मरे; लेकिन इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए देश की संसद में बहस हुई वंदे मातरम् पर।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी–भरकम जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर है, जहां आगामी मार्च–अप्रैल में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में चुनाव से पहले भी भाजपा के गठबंधन की सरकार थी और वहां उसे मिली जीत पर कई सवाल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का मैदान उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उस चुनौती को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग तो अपने काम में जुटा ही है और मोदी भी अपने अभियान जुट गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने शुरुआत संसद से की है और मुद्दा बनाया वंदे मातरम् को।

अपने राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करने में नरेन्द्र मोदी का कोई सानी नहीं है। चूंकि वंदे मातरम् की रचना बंगाल की धरती पर हुई थी और उसके रचयिता थे बंगाल के कवि–उपन्यासकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। उनके पांच छंदों वाले इस गीत के पहले दो छंदों को ही भारत के संविधान निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को उ मीद थी कि वे संसद में बहस के दौरान इस गीत में कांट–छांट करने के लिए विपक्ष की, खास तौर पर कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए अपनी पार्टी को देशभक्त और बांग्ला अस्मिता का पहरुआ साबित कर सकेंगे। लोकसभा में बहस की शुरूआत करते हुए मोदी और उनकी पार्टी ने यही करने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनका यह दांव पूरी तरह उलटा पड़ गया।

नरेन्द्र मोदी वैसे तो अपने सभी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को अपने से दोयम मानते हैं और ऐसा वे समय–समय पर परोक्ष रूप से जताने की कोशिश भी करते हैं, परन्तु देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू से तो उन्हें स त नफरत है, जिसे वे खुलकर व्यक्त करने में कोई कोताही नहीं करते। वंदे मातरम् पर बहस के दौरान भी इतिहास संबंधी अपने अधकचरे ज्ञान का परिचय देते हुए उन्होंने नेहरू और कांग्रेस को निशाना बनाया और खूब अनर्गल आरोप लगाए। उन्हीं की देखा–देखी उनकी पार्टी के दूसरे वक्ताओं ने भी ऐसा ही किया।

दरअसल इतिहास संबंधी किसी भी मुद्दे पर बोलते वक्त मोदी को ऐतिहासिक तथ्यों से कोई मतलब नहीं रहता। चूंकि मीडिया लगभग पूरी तरह उनके ताबे में है, इसलिए उनसे कभी कोई सवाल नहीं करता है। सत्ता के बल पर अनैतिक तरीके से हासिल इस सुविधा का वे भरपूर फायदा उठाते हुए जो मन में आता है, बोल देते हैं। ऐसा ही उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी करते हैं।

वंदे मातरम् पर बहस के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया। संभवत= विपक्षी नेताओं को मोदी के ऐसा करने का अंदाजा था, इसलिए वे पूरी तैयारी से सदन में आए थे। विपक्ष की ओर से तरुण गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, ए. राजा, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, असदउद्दीन ओवैसी आदि वक्ताओं ने ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों के जरिये प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं के तथ्यहीन भाषणों के धुर्रे बिखेर दिए। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस बार भी जोरदार तरीके से हुआ। अपनी पार्टी को देशभक्ति का अकेला झंडाबरदार साबित करने के चक्कर में मोदी और भाजपा के दूसरे नेता अपने राजनीतिक और वैचारिक पुरखों के पापों का पिटारा खुलवा बैठे। विपक्षी वक्ताओं ने मोदी को याद दिलाया कि देश की आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी बने हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस समय विभिन्न धाराओं के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले लाठी–गोली खा रहे थे तब आरएसएस और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों की फौज में भारतीयों को भर्ती करने का अभियान चला रखा था और डेढ़ लाख भारतीयों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराया था।

विपक्षी वक्ताओं ने मोदी और उनकी पार्टी को यह भी याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सावरकर की हिंदू महासभा जिन्नाह की मुस्लिम लीग के साथ तीन प्रांतों– बंगाल, सिंध और उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में साझा सरकार का हिस्सा बनी हुई थी। मोदी को यह भी याद दिलाया गया कि आरएसएस ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार किया था और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन% को ब्रिटिश शासक की स्तुति में लिखा हुआ बताते हुए उसे राष्ट्रगान मानने से इनकार किया था।

दरअसल मोदी और उनकी पार्टी को महात्मा गांधी और नेहरू का इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान या आजादी के बाद भी कभी आरएसएस और हिंदू महासभा के नेताओं को गद्दार या देशद्रोही नहीं कहा। वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे और लोग उन पर भरोसा भी कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आरएसएस और भाजपा के लिए उस टैग को अपने गले से हटा पाना आज तक मुश्किल होता। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से मोदी और उनकी पार्टी को यह भी बताया कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पांच लोगों की एक समिति ने लिया था जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद शामिल थे। मोदी को यह भी याद दिलाया गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1936 में वंदे मातरम् का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह नारा लगाने वाले को कोड़ों की सजा दी जाती थी। मोदी से पूछा गया कि वे बताएं कि आरएसएस और हिंदू महासभा के कितने लोग वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए जेल गए थे और उन्होंने सजा भुगती थी? पूरी बहस के दौरान स्पीकर ओम बिड़ला की निष्पक्षता का पलड़ा हमेशा की तरह सत्ता पक्ष की तरफ़ ही झुका रहा। प्रधानमंत्री सहित सत्ता पक्ष के हर वक्ता के भाषण को उन्होंने मुग्ध भाव से सुना लेकिन विपक्ष के लगभग हर वक्ता के भाषण के दौरान उन्होंने टोका–टाकी करते हुए उनके भाषण की लय को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बावजूद विपक्षी वक्ता तथ्यों और तर्कों के जरिये सत्ता पक्ष को बगलें झांकने के लिए मजबूर करने में सफल रहे। कुल मिलाकर आम बोल–चाल की भाषा में कहें तो वंदे मातरम् पर बहस में सरकार को लेने के देने पड़ गए। कहावत है कि मियांजी गए थे नमाज़ अदा करने लेकिन रोज़े गले पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ।

विविध समाचार

बागवानों को सेब खरीद बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी : सीएम सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के अंतर्गत वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में खरीदे गए सेबों के बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सेब उत्पादकों के खातों में भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएस के अंतर्गत 30 बैग तक सेब बेचने वाले उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब बेचने वाले उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वर्तमान सीजन में एमआईएस के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना (एचएमआईएस) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सेब खरीद से लेकर उसके प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेगा, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित होगी। सेब उत्पादकों को पोर्टल पर आधार संख्या, भूमि संबंधी विवरण और बैंक खाते की जानकारी देकर पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही वे अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट भी बुक कर सकेंगे, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी। खरीद और भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी उत्पादकों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने खरीद सीजन के दौरान सभी संग्रहण केंद्रों (कलेक्शन सेंटर) पर उत्पादकों की सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की गई है ताकि बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान, बागवानी सचिव सी. पॉलरासु, निदेशक डिजिटल प्रौद्यागिकी एवं नवाचार डॉ. निपुण जिंदल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी. सी. राणा, बागवानी निदेशक सतीश कुमार तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को विकास, आस्था और आधुनिक कनेक्टिविटी का नया युग दिया : तरुण चुग

चंडीगढ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ को विकसित भारत की यात्रा का ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। चुग ने कहा कि पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीवंत जीत है। उन्होंने कहा कि 3,200 हॉर्सपावर के साथ दुनिया की सबसे शक्तिशाली, 10 कोचों के साथ सबसे लंबी और 2,600 यात्रियों की क्षमता के साथ सबसे अधिक यात्री क्षमता वाली यह ट्रेन केवल जल वाष्प उत्सर्जित करती है, जो पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज पूरा विश्व भारत की इस रेल क्रांति को देख रहा है। चुग ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन के साथ–साथ प्रधानमंत्री जी ने लगभग ₹. 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर देश को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से दिल्ली से कटरा तक का सफर अब 14 घंटे की बजाय मात्र 6 घंटे में पूरा होगा। चुग ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे माता वैष्णो देवी और सच्चखंड हरिमंदिर साहिब तक हाई–स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो आस्था और विकास का अभूतपूर्व संगम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ही आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक अवसंरचना एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पंजाब को ₹. 5,500 करोड़ की रेल एवं सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक–करतोली नई रेल लाइन का उद्घाटन पंजाब की कनेक्टिविटी का नया अध्याय है, जबकि अमृतसर (छेहरटा)–वाराणसी एक्सप्रेस गुरु नगरी को काशी से जोड़ते हुए संत रविदास जी महाराज की पावन परंपरा को समर्पित है। चुग ने कहा कि जालंधर कैंट और मुक्तसर समेत देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन तथा 25.24 किलोमीटर लंबे 6 लेन दक्षिणी लुधियाना बाईपास से पंजाब के उद्योग, किसान और व्यापारी को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगी। चुग ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पंजाब के विकास और कल्याण के लिए ₹. 4.13 लाख करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता प्रदान कर सिद्ध कर दिया है कि पंजाब का विकास केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में ₹. 43,527 करोड़ के नेशनल हाईवे और 34,488 करोड़ का रेल आधुनिकीकरण किया गया है। चुग ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजाब के 11 लाख से अधिक किसानों को सीधे 6,552 करोड़ का लाभ मिला है, MSP खरीद हेतु 2.60 लाख करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि एम्स बठिंडा और 565 से अधिक जन औषधि केंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी सोच के प्रतीक हैं। चुग ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक ओर केंद्र सरकार पंजाब पर विकास की वर्षा कर रही है, वहीं दूसरी ओर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार केवल झूठे विज्ञापनों और आत्मप्रचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार में न कानून व्यवस्था संभली, न नशे के कारोबार पर लगाम लगी और न ही जनता से किए गए किसी वादे को पूरा किया गया। चुग ने कहा कि पंजाब की जनता अब आम आदमी पार्टी के झूठ और धोखे को भली–भांति समझ चुकी है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका पूरा हिसाब लेगी।

एसजेवीएन फाउंडेशन ने रामपुर आयुर्वेदिक अस्पताल को दी अत्याधुनिक जांच मशीन

शिमला। शिमला जिले के रामपुर बुशहर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अब मरीजों को रक्त संबंधी कई जरूरी जांचें पहले से अधिक तेजी और बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो सकेंगी। एसजेवीएन फाउंडेशन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अस्पताल को फुली ऑटो बायो केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन उपलब्ध कराई है। शुक्रवार को रामपुर जल विद्युत स्टेशन (एचपीएस), बायल के परियोजना प्रमुख ई. विकास मारवाह ने इस मशीन का शुभारंभ किया। अस्पताल में हर वर्ष करीब 40 हजार से 42 हजार बाह्य रोगियों (ओपीडी) और लगभग एक हजार भर्ती मरीजों (आईपीडी) का उपचार किया जाता है। यहां मरीजों को इलाज के दौरान कई आवश्यक जांचें निरूशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। नई मशीन लगने के बाद जांच की सुविधा अधिक तेज और सटीक होने की उम्मीद है। एसजेवीएन के अनुसार इस मशीन से शिमला जिले की रामपुर, कुमारसैन और ननखड़ी तहसीलों के अलावा किन्नौर जिले की निचार तथा कुल्लू जिले की निरमंड और आनी तहसीलों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। अस्पताल आने वाले मरीजों को कई जांचों के लिए अब बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर ई. विकास मारवाह ने कहा कि एसजेवीएन समाज के विकास और जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जांच मशीन उपलब्ध होने से मरीजों को विभिन्न परीक्षण जल्दी कराने की सुविधा मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीज भी अस्पताल में निरूशुल्क जांच सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पहल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाएगी।

छात्राओं का सामान्य ज्ञान मजबूत होना समय की मांग : खन्ना

होशियारपुर।पूर्व राज्यसभा सांसद एवं बाबा औगढ़ श्री फतेहनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट जैजों के चेयरमैन अविनाश राय खन्ना ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान जारी रखते हुए बाबा औगढ़ श्री फतेहनाथ गर्ल्स कॉलेज, जैजों की छात्राओं के लिए जनरल नॉलेज की पुस्तकें भेंट कीं। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को पुस्तकों का महत्व बताते हुए नियमित अध्ययन और समसामयिक विषयों की जानकारी रखने के लिए प्रेरित किया। खन्ना ने कहा कि आज का युग ज्ञान और प्रतिस्पर्धा का है। केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहने के बजाय विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विषयों की भी व्यापक जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनरल नॉलेज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का महत्वपूर्ण आधार होने के साथ–साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ बनाती है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं और नियमित अध्ययन से ही जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। छात्राओं को चाहिए कि वे पढ़ने की आदत विकसित करें और प्रत्येक दिन कुछ समय सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक विषयों के अध्ययन के लिए अवश्य निकालें। कॉलेज प्रबंधन ने अविनाश राय खन्ना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा भेंट की गई पुस्तकें छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगी तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विशेष सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ–साथ उन्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष अश्वनी खन्ना, ज्योति भूषण सूद, कॉलेज की प्रिंसिपल कर्मजीत कौर, कालेज प्रबंधन सदस्य एवं बड़ी संख्या में छात्राएँ उपस्थित रहीं।

हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, चंबा में चलती गाड़ी पर दरका पहाड़, मौत के मुंह से बचे वाहन सवार

चंबा। हमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। चंबा जिले के चुवाड़ी–भराड़ी मार्ग पर शनिवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन ने सड़क का बड़ा हिस्सा बहा दिया। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार अचानक मलबे की चपेट में आ गई और बीच सड़क पर फंस गई। राहत की बात यह रही कि वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 8 बजे पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा। भूस्खलन इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गहरी खाई में समा गया। घटना के बाद चुवाड़ी–भराड़ी मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग ने तुरंत दो जेसीबी मशीनों को राहत कार्य में लगाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में फंसी कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ ही सड़क से मलबा हटाने और मार्ग को दोबारा चालू करने का अभियान तेज कर दिया गया है। मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ–साथ लंबी दूरी के यात्रियों को भी घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। जरूरी काम से निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई वाहनों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भूस्खलन से सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण राहत कार्य में दिक्कत आ रही है, लेकिन मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर काम जारी है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि मौसम सामान्य होते ही मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

पीएम मोदी द्वारा 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन

श्री आनंदपुर साहिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का वर्चुअल उद्घाटन कर एक नया इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार की 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पंजाब के पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन को भी इस बड़ी सौगात में शामिल किया गया है। इस खास मौके पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने इसे राज्य के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिल से आभार जताया।

डॉ. शर्मा ने कहा कि 29 करोड़ रुपए की भारी लागत से तैयार हो रहा यह रेलवे स्टेशन अब खालसाई वास्तुकला और हमारी महान विरासत का अनोखा प्रतीक बनेगा, जिसे देखते ही हर श्रद्धालु को इस पावन धरती की महानता का अहसास होगा। डॉ. सुभाष शर्मा ने जनसभा में जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा चुनाव के दौरान किए गए अपने हर वादे को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। उन्होंने पंजाब के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए बताया कि मोहाली में स्थित सेमीकंडक्टर लैब के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 4500 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर कर दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से पंजाब में चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और तकनीकी विकास के साथ–साथ राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों नए अवसर पैदा होंगे। संबोधन के दौरान डॉ. सुभाष शर्मा ने क्षेत्र के लोगों की एक और बड़ी और पुरानी मांग पूरी होने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय ने नंगल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिससे अब स्थानीय लोगों और यात्रियों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।

कांग्रेस सरकार की नीतियों से उद्योग और शिक्षा व्यवस्था हुई प्रभावित : सिकंदर कुमार

शिमला। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण औद्योगिक विकास और शिक्षा व्यवस्था दोनों प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय घोषणाओं और प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है तथा उद्योगों और शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। डॉ. सिकंदर कुमार शुक्रवार को शिमला के समरहिल में आयोजित "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा ने प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 25 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। उनके अनुसार प्रदेश के करीब 8,000 बूथों पर दो लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के समय में विभिन्न समाचार रिपोर्टों में सरकार की नीतियों की कमियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बल्क ड्रग पार्क से जुड़े उद्योगों को तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रही है, लेकिन केवल ऐसी घोषणाओं से उद्योग स्थापित नहीं होंगे। उनका कहना था कि निवेशकों को स्थिर औद्योगिक नीति, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, अच्छी सड़कें और पारदर्शी प्रशासन चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण निवेश का माहौल कमजोर हुआ है और उद्योगों का विस्तार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार की आलोचना की। डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई प्राथमिक विद्यालयों में प्री–प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षक अपनी जेब से हर महीने करीब 2,500 से 3,000 रुपये खर्च कर अस्थायी शिक्षक रखने को मजबूर हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, बुधवार 16 सितंबर 2026

ग्वालियर पहुंचने से पहले पकड़ा गया ट्रक, २१४ किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार

भुवनेश्वर १५/०९ (संवाददाता): ओडिशा के भुवनेश्वर से कथित तौर पर अवैध गांजा लेकर ग्वालियर जा रहे एक ट्रक को झांसी के बबीना इलाके में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रोक लिया। ट्रक से 214 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। टीम ने ट्रक चालक समेत दो लोगों को गिरफ़्तार किया है। दोनों से गांजे की आपूर्ति करने और खेप प्राप्त करने वालों के बारे में पूछताछ की जा रही है।भौगोलिक संदर्भ पुलिस के अनुसार, संदिग्ध ट्रक भुवनेश्वर से करीब 1,227 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। दावा है कि आरोपित अलग-अलग राज्यों से गुजरते हुए जांच चौकियों और टोल प्लाजा से बचने का प्रयास करते रहे। ट्रक को ग्वालियर पहुंचना था और वह अपने कथित गंतव्य से लगभग 100 किलोमीटर दूर था, तभी संयुक्त टीम ने उसे बबीना के पास रोक लिया। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बबीना थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम सुकुवा-धुकुवा रोड पर नयाखेड़ा स्थित एक फार्महाउस के पास हाईवे पर वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम को वहां से गुजर रहे एक ट्रक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिसकर्मियों ने वाहन को रोककर चालक और उसमें मौजूद दूसरे व्यक्ति से पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ट्रक की तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहन के भीतर बड़ी मात्रा में गांजा मिला। बरामद मादक पदार्थ का वजन कराने पर उसकी कुल मात्रा 214 किलोग्राम निकली। पुलिस ने गांजा और ट्रक को कब्जे में लेते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ़्तार कर लिया। बरामद गांजे की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रकाशित रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से इसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.07 करोड़ रुपये बताया गया है। पुलिस का दावा है कि गांजे की खेप भुवनेश्वर से ग्वालियर पहुंचाई जा रही थी। संयुक्त टीम अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांजे को भुवनेश्वर में किस स्थान से ट्रक में रखा गया था। इसके अलावा खेप ग्वालियर में किस व्यक्ति को सौंपी जानी थी और इसके बदले चालक व उसके साथी को कितनी रकम मिलने वाली थी, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस आरोपितों के मोबाइल फोन, कॉल विवरण और डिजिटल लेन-देन से संबंधित जानकारी की पड़ताल कर सकती है। वाहन के यात्रा मार्ग, टोल रिकॉर्ड, ईंधन भरवाने के स्थान और रास्ते में रुकने वाले ठिकानों का विवरण भी पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि रास्ते में आरोपितों की किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात हुई थी या नहीं। ट्रक ने करीब 1,227 किलोमीटर की दूरी तय की और कई राज्यों की सीमाओं से गुजरते हुए बबीना तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने मुख्य जांच स्थलों और टोल प्लाजा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया। हालांकि ट्रक ने वास्तविक रूप से किन-किन मार्गों से यात्रा की और किन स्थानों पर जांच से बचने का प्रयास किया, इसकी विस्तृत पुष्टि की जा रही है। गांजे की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद इसके पीछे अंतरराज्यीय नेटवर्क की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। केवल चालक और उसके साथी की गिरफ़्तारी से मादक पदार्थ की पूरी आपूर्ति श्रृंखला सामने नहीं आती। पुलिस के सामने गांजा उपलब्ध कराने वाले, परिवहन की व्यवस्था करने वाले और अंतिम खरीदार तक पहुंचने की चुनौती होगी। मादक पदार्थों की तस्करी में मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल नया नहीं है। लंबी दूरी तय करने वाले ट्रकों में वैध सामान के साथ अवैध सामग्री छिपाकर ले जाने के मामले सामने आते रहे हैं। बड़े ट्रक अनेक राज्यों से होकर गुजरते हैं और सामान्य मालवाहक वाहन की तरह दिखाई देते हैं। इसी का फायदा उठाकर तस्कर कथित रूप से पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने का प्रयास करते हैं। इस मामले में ट्रक ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर पहले ही पकड़ लिया गया। पुलिस का मानना है कि यदि वाहन जांच से निकल जाता तो यह बड़ी खेप अपने निर्धारित ठिकाने तक पहुंच सकती थी। वहां से गांजे को छोटी-छोटी मात्रा में अलग-अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके संबंध में आधिकारिक निष्कर्ष आगे की पूछताछ और साक्ष्यों के बाद सामने आएगा। पुलिस ट्रक के पंजीकरण और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जाएगा कि वाहन किस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है और मालिक को उसमें गांजा ले जाए जाने की जानकारी थी या नहीं। यदि वाहन किसी परिवहन कंपनी से जुड़ा मिलता है तो बुकिंग और माल से संबंधित दस्तावेज भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जब्त पदार्थ के नमूने लेकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षण के लिए भेजे जा सकते हैं। साथ ही वजन, पैकिंग और बरामदगी से संबंधित रिकॉर्ड तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपितों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल दोनों गिरफ़्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

आरएसपी में पीसीपी–2024 पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया

राउरकेला १५/०९ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) की सीएसआर पहल के तहत जलदा %सी% ज़्लॉक में स्थापित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) संयंत्र के परिधीय क्षेत्रों से महिलाओं के लिए एक स्थायी आजीविका मंच के रूप में लगातार उभर रहा है। सेंटर को हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज सिलने के ऑर्डर मिले हैं और पिछले दो महीनों के दौरान लगभग 50,000 रुपये का लाभ दर्ज किया है। टीसीपीसी की स्थापना अपने परिधीय क्षेत्रों में महिलाओं के बीच कौशल विकास और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी। यह पहल मई 2025 में जलदा पुनर्वास कॉलोनी की 15 महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। इस कार्यक्रम को आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा प्रतिभागियों की पहचान और जुटाने के लिए ग्राम उत्थान के समर्थन से सुगम बनाया गया था, जबकि उषा सिलाई के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण शुरू में बुनियादी सिलाई पर केंद्रित था और धीरे-धीरे उन्नत परिधान बनाने और मूल्य वर्धित तकनीकों की ओर बढ़ा। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उपयोगिता उत्पादों जैसे शर्ट, पतलून, महिलाओं के कपड़े, कपड़े के बैग, एप्रन, जैकेट आदि के साथ-साथ कढ़ाई, एप्लिक, कट-वर्क, रज़ाई, पैचवर्क और अन्य सजावटी तकनीकों को सिलाई करने में प्रशिक्षित किया गया था।इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण से वास्तविक उत्पादन और बाज़ार से जुड़ी गतिविधियों की ओर बढ़ना रहा है। महिलाओं ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही उत्पादन के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिसमें आंगनवाड़ी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलना भी शामिल था। आगे के प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग के साथ, सेंटर ने अपने उत्पाद रेंज और ग्राहक आधार का विस्तार किया और बाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ढांचे के तहत पंजीकरण प्राप्त किया। राष्ट्रीय झंडे के लिए हाल के ऑर्डर ने केंद्र के लिए एक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान किया है। विकास केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित रहने के बजाय बाज़ार से जुड़े उत्पादन के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न करने की टीसीपीसी की क्षमता को दर्शाता है। आरएसपी की सीएसआर पहल ने कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, मार्गदर्शन और आजीविका के अवसरों को एक साथ लाकर इस परिवर्तन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीसीपीसी की स्थापना करके और प्रशिक्षण के क्रमिक दौरों की सुविधा प्रदान करके, आरएसपी ने एक ऐसा मंच बनाने में मदद की है जहां प्रशिक्षित महिलाएं उत्पादन के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकती हैं, ऑर्डर ले सकती हैं और धीरे-धीरे एक स्वतंत्र सामुदायिक उद्यम का निर्माण कर सकती हैं।

पुलिस कार्रवाई में 24 आपराधिक मामलों वाला हिस्ट्रीशीटर घायल

संबलपुर १५/०९ (संवाददाता): सदर पुलिस इलाके में कैनाल रोड पर सुडुंगा जंगल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 24 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर घायल हो गया। सुनापाली के रहने वाले आरोपी मोहज़्मद इरफान के बाएं पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए बुर्ला के VIMSAR अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 5.45 बजे पुलिस की एक टीम ने इरफान और उसके दो साथियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए रोका। पुलिस टीम को देखते ही इरफान ने भागने की कोशिश में तीन राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी दो राउंड फायरिंग की। एडिशनल SP अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर के साथियों को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन इरफान मौके से भाग निकला। भागते समय उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें इरफान को गोली लग गई। बाकी दो आरोपियों के नाम मोहज़्मद अरमान (28) और दीपक कुमार (20) हैं। मौके से एक पिस्तौल, कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद किए गए। आरोपी और उसके साथियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी ज़ब्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि इरफान पश्चिमी ओडिशा के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज 24 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल है। इन मामलों में डकैती, लूट, एल्युमीनियम के तार की चोरी, सेंधमारी और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध शामिल हैं।

पान के विवाद में महिला की हत्या

मयूरभंज १५/०९ (संवाददाता): पुलिस ने रविवार को बताया कि मयूरभंज ज़िले की बाराकंद पंचायत के तहत आने वाले टियांसी गाँव में कथित तौर पर पान के एक टुकड़े को लेकर 57 साल की एक महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान 62 वर्षीय अनंत नाइक की पत्नी बिलासी नाइक के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला (356/26) दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, उसी गाँव के रहने वाले 37 वर्षीय धीरेन नाइक अक्ज़र अनंत से पान देने के लिए कहते थे।

पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी पर बड़ा एक्शन, छह आरोपी गिरफ्तार

मलकानगिरी १५/०९ (संवाददाता): मलकानगिरी के डिविज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर (छ्ह्र्ह) किरण ने रविवार को बताया कि मलकानगिरी फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छह तस्करों को गिरफ़्तार किया है और उनके पास से लगभग दो किलो पैंगोलिन के शल्क ज़ब्त किए हैं।

ख़ास जानकारी मिलने पर, मलकानगिरी रेंज और मैथिली रेंज के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने पद्मगिरी-पांडरीपानी रोड पर छापा मारा और तीन अलग-अलग बाइकों पर जा रहे छह लोगों से लगभग दो किलो वज़न के 352 पैंगोलिन शल्क ज़ब्त किए। अधिकारियों ने वन्यजीव तस्करों के पास से पाँच मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त किए। छ्ह्र्ह ने आगे बताया कि गिरफ़्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि तस्करी के बारे में और जानकारी मिल सके, जैसे कि पैंगोलिन शल्क कहाँ से लाए गए थे और उन्हें किसे और कहाँ बेचा जाना था।उन्होंने बताया कि पैंगोलिन शल्क की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा।

धर्मशाला में झड़प के बाद राजनीतिक बयानबाजी, दोनों पक्षों ने धरना दिया

भुवनेश्वर १५/०९ (संवाददाता): धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक झड़प से तनाव बढ़ गया है, रविवार को हुई हिंसा के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक प्रणब बलबंतराय के नेतृत्व में क्ष्छ्ष्ठ कार्यकर्ताओं ने छ्ठ्ठ कैंप ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू की गिरफ़्तारी की मांग की।

यह विरोध प्रदर्शन रविवार को धर्मसाला में एक फार्महाउस पर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हुआ है।

आरोप है कि झड़प तब शुरू हुई जब विधायक साहू के समर्थकों ने बीजद कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, पर हमला किया, जो बलबंतराय के फार्महाउस पर पार्टी की मीटिंग कर रहे थे। बीजद ने 100 से ज़्यादा साहू समर्थकों के नाम का एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक महिला के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की। बलबंतराय और उनके समर्थक रात भर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमलावरों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलबंतराय ने कहा, हमें जिला पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब तक आरोपियों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

इस बीच, साहू के समर्थकों ने जेनापुर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि बलबंतराय के समर्थकों ने हिंसा शुरू की थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है।

आरएसपी की सीएसआर पहल स्थायी आजीविका के माध्यम से महिलाओं को बनाती है सशक्त

राउरकेला १५/०९ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) की सीएसआर पहल के तहत जलदा सी ज़्लॉक में स्थापित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) संयंत्र के परिधीय क्षेत्रों से महिलाओं के लिए एक स्थायी आजीविका मंच के रूप में लगातार उभर रहा है। सेंटर को हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज सिलने के ऑर्डर मिले हैं और पिछले दो महीनों के दौरान लगभग 50,000 रुपये का लाभ दर्ज किया है। टीसीपीसी की स्थापना अपने परिधीय क्षेत्रों में महिलाओं के बीच कौशल विकास और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी। यह पहल मई 2025 में जलदा पुनर्वास कॉलोनी की 15 महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। इस कार्यक्रम को आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा प्रतिभागियों की पहचान और जुटाने के लिए ग्राम उत्थान के समर्थन से सुगम बनाया गया था, जबकि उषा सिलाई के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।प्रशिक्षण शुरू में बुनियादी सिलाई पर केंद्रित था और धीरे-धीरे उन्नत परिधान बनाने और मूल्य वर्धित तकनीकों की ओर बढ़ा। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उपयोगिता उत्पादों जैसे शर्ट, पतलून, महिलाओं के कपड़े, कपड़े के बैग, एप्रन, जैकेट आदि के साथ-साथ कढ़ाई, एप्लिक, कट-वर्क, रज़ाई, पैचवर्क और अन्य सजावटी तकनीकों को सिलाई करने में प्रशिक्षित किया गया था।इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण से वास्तविक उत्पादन और बाज़ार से जुड़ी गतिविधियों की ओर बढ़ना रहा है। महिलाओं ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही उत्पादन के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिसमें आंगनवाड़ी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलना भी शामिल था। आगे के प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग के साथ, सेंटर ने अपने उत्पाद रेंज और ग्राहक आधार का विस्तार किया और बाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ढांचे के तहत पंजीकरण प्राप्त किया। राष्ट्रीय झंडे के लिए हाल के ऑर्डर ने केंद्र के लिए एक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान किया है। विकास केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित रहने के बजाय बाज़ार से जुड़े उत्पादन के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न करने की टीसीपीसी की क्षमता को दर्शाता है। आरएसपी की सीएसआर पहल ने कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, मार्गदर्शन और आजीविका के अवसरों को एक साथ लाकर इस परिवर्तन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीसीपीसी की स्थापना करके और प्रशिक्षण के क्रमिक दौरों की सुविधा प्रदान करके, आरएसपी ने एक ऐसा मंच बनाने में मदद की है जहां प्रशिक्षित महिलाएं उत्पादन के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकती हैं, ऑर्डर ले सकती हैं और धीरे-धीरे एक स्वतंत्र सामुदायिक उद्यम का निर्माण कर सकती हैं।